एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 04, अंक: 02 (मार्च-अप्रैल, 2024)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारते हुए: भारतीय पशुपालन योजनाओं का परिचय

(*ली. परीकुंवर एल परमार)
एम.वी.एससी., कामधेनु यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात
*संवादी लेखक का ईमेल पता: parikunwar@gmail.com

पशुपालन कृषि के महत्व को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे सिर्फ आय में वृद्धि होती है, बल्कि अनेक लोगों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होता है। भारत में पशुपालन के लिए कुछ प्रमुख राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। भारत दुनिया के दुग्ध उत्पादक देशों में अग्रणी है और इसकी बड़ी गोजातीय आबादी है। इससे दूध और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि होती है, जो बढ़ती आबादी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेयरी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है, विशेष रूप से सीमांत और महिला किसानों के लिए, जो अपनी आजीविका के लिए इसे मुख्य रूप से आधार मानते हैं। अधिकांश दूध का उत्पादन छोटे, सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों द्वारा पाले गए जानवरों द्वारा किया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संवास्थ्य और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

1. स्वस्थ पशु सुरक्षित पशुपालक योजना

"स्वस्थ पशु सुरक्षित पशुपालक योजना" नामक सरकारी योजना को 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के किसानों और पशुपालकों को सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, निःशुल्क दुर्घटना बीमा दिया जाता है, जिसे भारत सरकार और निगम का आर्थिक सहयोग के तहत ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रदान करती है। साथ ही, पशुओं के लिए उच्च स्तर का कैल्शियम भी उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, पशुपालकों को स्पेशल गोल्ड दूधधारा सीरप खरीदने पर निःशुल्क दुर्घटना बीमा प्राप्त करने का विकल्प होता है। यदि कोई पशुपालक एक साथ तीन स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम सीरप खरीदता है, तो उसे और अधिक बीमा कवर प्राप्त होता है।

2. आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय पशुपालन निगम ने 2020 में "आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम" की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण युवाओं को बकरी, मुर्गी, खरगोश, सुअर, कड़कनाथ फार्म, डेयरी फार्म आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर, अभ्यार्थी को प्रमाण-पत्र भी दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के बाद, युवा स्वरोजगार करते हैं और निगम द्वारा स्वरोजगार कार्यक्रम में युवाओं के लिए लोन की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

3. पैरावेट सह कृत्रिम गर्भाधान

भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड और राजस्थान सरकार के सहयोग से, राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम की ओर से, ग्रामीण परिवेश के दसवीं पास छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण पेरावेट सह कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत, छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, बधियाकरण आदि कार्यों में योग्य होते हैं और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने का संभावना होता है।

4. एकीकृत कृषि, डेयरी, ऊर्जा व भूमि विकास कार्यक्रम (INFADEL)

भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड" का यह योजना एक प्रमुख पहल है, जिसमें पशुपालकों, किसानों और समाज के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपयोगी और विकासात्मक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शामिल है। इस योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं:

- एकीकृत खेती (प्राकृतिक संसाधनों का एकीकृत उपयोग): इसमें खेती के साथ साथ डेयरी (दूध उत्पादन, पाश्चराइजेशन और पैकेजिंग) संयंत्र की स्थापना, प्राकृतिक सौर ऊर्जा उत्पादन, जैविक खेती, बंजर भूमि का विकास, और ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना शामिल है।
- पशुपालन का विकास: इसमें पोल्ट्री फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, और डेयरी फार्मिंग के लिए प्रोत्साहन, ऑर्गेनिक फ्लोर मिल प्लांट और जैविक सरसों मिल संयंत्र की स्थापना शामिल है।
- "पशुपालक उन्नति केंद्र" की स्थापना: इसके माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें उन्नत तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाएगा।
- एकीकृत खेती एक कृषि प्रणाली है जो खेती के घटकों को एक-दूसरे का समर्थन करती है। बंजर भूमि विकास के लिए इसमें काम किया जा रहा है, जो भारत की कुल भूमि का तीसरा हिस्सा है।
- दूध उत्पादन में भारत दुनिया के शीर्ष दूध उत्पादक देशों में से एक है, और इसकी आवश्यकता बढ़ रही है। मुर्गा और बकरी पालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

5. अपना भारत अपना बाजार मिशन

अपना भारत अपना बाजार मिशन" एक महत्वपूर्ण पहल है जो विदेशी कंपनियों के भारतीय ऑनलाइन खुदरा बाजार में एकाधिकार को दूर करने के लिए शुरू की गई है। इस मिशन के माध्यम से "अपना बाजार" पोर्टल को प्रत्येक राज्य में पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय खुदरा बाजार को आत्मनिर्भर बनाना, खुदरा व्यापार को बढ़ाना, नियमितता प्रदान करना और भारतीय मुद्रा को भारत के विकास कार्यों तक पहुँचाना।

इस पहल के तहत, "अपना बाजार" पोर्टल को राज्यों के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रसारित किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को स्थानीय उत्पादों और सेवाओं की अधिक सुविधा मिल सके। यह भारतीय उद्यमियों को विदेशी रक्षाबंधन की चुनौती का सामना करने में मदद करेगा और स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देगा। इससे भारतीय खुदरा बाजार की स्थायिता और विकास में मदद मिलेगी, जो अब उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर हो रहा है।